NT>

Title: Regarding recovery of Non-performing Assets (N.P.A.) from big industrialists in the country.

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान दिनांक 01.12.2002 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं : "The Great Indian Bank Robbery"

उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये चंद उद्योगपतियों के एन.पी.ए. हैं। हमारे राट्रीयकृत बैंकों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिये। स्वयं हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस राशि के बारे में कहा है : "This is not debt, this is loot."

उपाध्यक्ष जी, यह उनका बयान है। केन्द्र शासन ने जो प्रयास किये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। केन्द्र शासन ने चन्द राज्यों में डॅट रिकवरी ट्रिब्युनल्स बनाये हैं। डी.आर.टी. में 56,988 मामले दर्ज हैं जिनसे एक लाख आठ हजार छ: सौ पचपन करोड़ रुपये वसूलने हैं लेकिन मार्च, 2002 तक मात्र 4736 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। उन चंद उद्योगपतियों में से 1012 करोड़ रुपये लॉयड ग्रुप के नाम, 846 करोड़ रुपये मॉडर्न ग्रुप के नाम और 705 करोड़ रुपये परस रामपुरिया ग्रुप के नाम वसूलने हैं। यह लम्बी सूची है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन चंद उद्योगपतियों के एन.पी.एज. ज़ब्त किये जायें और देश की जनता का पैसा राट्रीयकृत बैंकों को वापस दिलवाया जाये। अगर यह राशि वसूल की जाती है तो इससे दो साल के लिये रक्षा बजट बन सकता है या हम इस देश में हर प्रदेश में एक एक्सप्रैस हाईवे बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा हो और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर चर्चा करें जिससे इस समस्या का हल निकले और कोई कानून बनाया जा सके ताकि हमारा पैसा राट्रीयकृत बैंकों में आ सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को इस बात से सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is allowed to associate himself with what the hon. Member has said.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री लक्ष्मण सिह जी के साथ एसोसिएट करने के लिये श्री शिवराज सिंह जी, आपको बधाई।